



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022021-225517  
CG-DL-E-26022021-225517

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]  
No. 71]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2021/फाल्गुन 7, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2021/PHALGUNA 7, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

मामला सं. ए डी (एस एस आर)- 19/2020

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'टायरों के लिए टायर क्योरिंग प्रेसस' के आयातों के संबंध में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/37/2020-डीजीटीआर.—मैसर्स लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड (जिसे यहां इसके बाद से “आवेदक” भी कहा गया है) ने, (जिसे यहां इसके बाद से “अधिकारी” भी कहा गया है) समय- समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद से “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय- समय पर यथा संशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'टायरों के लिए टायर क्योरिंग प्रेसस', जिसे टी सी पी के नाम से भी जाना जाता है (जिसे यहां इसके बाद से “संबद्ध वस्तुएं” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पी यू सी” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच की निर्णयिक समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने चीन पीआर से उत्पन्न और निर्यात किए गए विषय वस्तुओं की डंपिंग जारी रखने और एंटी डंपिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का आरोप लगाया है, और चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तुओं के आयात पर सूर्योस्त की समीक्षा जांच के लिए अनुरोध किया है।

### **क. पृष्ठभूमि**

3. प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2009 में चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच शुरू की गई थी। अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना अक्टूबर 2009 में जारी किए गए थे, जिसमें निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गयी थी। प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर दिनांक 8 जनवरी 2010 की अधिसूचना सं. 01/2010- सीमाशुल्क के तहत निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था।
4. दिनांक 23 मई 2011 को एक मध्यावधिक समीक्षा जांच शुरू की गई और दिनांक 29 मार्च 2012 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए जिसमें पाटन रोधी शुल्क की सीमा और दायरे से साइकल टायरों की क्योरिंग के लिए सिक्स डे लाइट क्योरिंग प्रेस को बाहर करने की सिफारिश की गई। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. 26/2012- सीमा शुल्क (ए डी डी) के तहत उत्पाद को छूट प्रदान की।
5. दिनांक 7 जनवरी 2015 को एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई। समीक्षा के परिणामों के लंबित रहते अधिसूचना सं. 06/2015- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 7 जनवरी 2016 तक एक वर्ष की अवधि के लिए शुल्कों का विस्तार किया गया। प्राधिकारी ने दिनांक 5 जनवरी 2016 को अन्तिम जांच परिणाम जारी किए जिसमें शुल्कों को 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की सिफारिश की गई। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 मार्च 2016 की अधिसूचना सं. 11/2016- सीमा शुल्क (ए डी डी) के तहत शुल्क बढ़ाए गए।

### **ख. विचाराधीन उत्पाद**

6. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि विगत निर्णायक समीक्षा जांच में परिभाषित किया गया है, “टायर क्यूरिंग प्रेसस” है जिसे टायर वुल्केनाइजर अथवा टायरों के लिए रबर प्रोसेसिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें साइकल टायरों की क्योरिंग के लिए सिक्स डे लाइट क्योरिंग प्रेस शामिल नहीं है।
7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 84 के तहत वर्गीकृत किया गया है और इसका उप शीर्ष 84775100 है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।
8. घरेलू उद्योग ने पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए वर्तमान जांच के प्रयोजन से (क) उस टायर के डायामीटर, जिसे क्योर किया जाना है और (ख) क्या मशीन हाइड्रोलिक है या मैकेनिकल है, इस आधार पर पी सी एन को अपनाया है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार इस जांच के प्रयोजन से पी सी एन को अंतिम रूप देने के लिए इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां/ सुझाव दे सकते हैं।

### **ग. समान वस्तु**

9. आवेदकों ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं ओर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, निर्माण प्रक्रिया, और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन से आवेदक द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

### **घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

10. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। जैसा कि आवेदक द्वारा दावा किया गया है, उनका हिस्सा संबद्ध वस्तुओं के सकल घरेलू उत्पादन का करीब 88% है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातिक अथवा उत्पादक से अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित हैं। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग है और इस नियमावली के नियम 5 (3) के तहत स्थिति के मापदंड को पूरा करता है।

#### **ड. डंपिंग की पुनरावृत्ति की संभावना का आधार**

11. आवेदक ने दावा किया है कि चीन पीआर को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध । के पैराग्राफ-7 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए । आवेदक ने नियमों के एनेक्सचर । के पैरा 8 (2) का हवाला दिया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमों के अनुबंध । के पैरा 8 (3) के संदर्भ में विषय वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है । बाजार अर्थव्यवस्था में विचाराधीन उत्पाद की कीमतें या निर्मित मूल्य उपयुक्त तीसरे देश या भारत सहित ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को कीमतें न तो आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, विशेष रूप से उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए और न ही यह जानकारी किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकरण के पास उपलब्ध है । इस प्रकार, भारत में उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य प्रशासनिक खर्च और उचित मुनाफे को ध्यान में रखते हुए, भारत में भुगतान किए गए या देय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है । अलग-अलग प्रेस के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य तैयार किया गया है ।

12. आवेदक ने वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) लेनदेन के लिहाज से आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात मूल्यों का दावा किया है । महासागर भाड़ा, बीमा और अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा और अग्रेषण प्रभारों के लिए मूल्य समायोजन किया गया है ।

13. सामान्य मूल्य के अनुमानों और ऊपर उल्लिखित निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, डंपिंग मार्जिन का निर्धारण किया गया है । प्रत्येक प्रकार के प्रैरस के लिए अलग डंपिंग मार्जिन निर्धारित किया गया है । परिणामी भारित औसत डंपिंग मार्जिन सकारात्मक है । प्रथम दृष्ट्या इस बात के सबूत हैं कि उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत को निर्यात किया गया है, जिससे यह दर्शाया गया है कि चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तुओं को डंप की गई कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है ।

#### **च. क्षति और कारण लिंक की निरंतरता**

14. आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । विषयवस्तु से देश के सामानों के आयात की मात्रा निरपेक्ष रूप से पीओआई में वृद्धि हुई है । पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन खपत के संबंध में पीओआई के दौरान आयात में भी वृद्धि हुई है । आयात लागू ऐड के बिना घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे हैं । हालांकि आधार वर्ष से 2018-19 तक घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, लेकिन पीओआई के दौरान इसमें गिरावट आई है और इस तरह विषय देशों से विषय वस्तुओं की डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग असुरक्षित बना हुआ है ।

#### **छ. क्षति और आकस्मिक लिंक की पुनरावृत्ति की संभावना**

15. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा और कीमत, सकारात्मक क्षति मार्जिन, बिना पाटन रोधी शुल्क के कीमत कटौती और बिना पाटनरोधी शुल्क के घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर विचार करते हुए, पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं । इसके अलावा, आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन के उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण और आसानी से उपयोग करने योग्य उत्पादन क्षमताएं हैं और चीन के उत्पादक अत्यधिक निर्यात उन्मुखी हैं । प्रथम दृष्ट्या यह पाया गया है कि यदि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना है ।

#### **ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत**

16. घरेलू उद्योग द्वारा अपनी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्षात्कृत लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23 (1बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों के जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए तथा यह जांच करने के लिए कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं ।

**झ. संबद्ध देश**

17. संबद्ध जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

**अ. जांच की अवधि (पी ओ आई)**

18. आवेदक ने शुरू में 1 अप्रैल 2019 से 30 जून तक जांच की अवधि प्रस्तावित की थी, 2020 और अधिक जांच अवधि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक और जांच की अवधि। बाद में आवेदक ने पीओआई को 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ाने का अनुरोध किया और 30 जून, 2020 तक आंकड़े प्रस्तुत किए। प्राधिकरण हालांकि नियम 2 (डीए) को ध्यान में रखते हुए, और नियम 22 को स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल 2019 - 30 सितंबर 2020 (18 महीने) की अवधि को जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में निर्धारित करने के लिए उचित मानता है, और 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 और जांच की अवधि को इंजरी इन्वेस्टिगेशन पीरियड बताया। प्राधिकरण मानता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के एक पूर्ण लेखावर्ष को नियम और शामिल करने पर विचार करते हुए जांच की अवधि उचित है।

**ट. प्रक्रिया**

19. वर्तमान समीक्षा जांच में चीन जन. गण. के संबंध में दिनांक 29 मार्च 2016 की अधिसूचना सं. 11/2016- सीमा शुल्क (ए डी डी) के तहत जारी निर्णायक समीक्षा जांच के संबंध में अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

20. उपरोक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, और 20 के प्रावधानों को इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तनों के बाद लागू किया जाएगा।

**ठ. सूचना प्रस्तुत करना**

21. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्राचार ई-मेल पतों अर्थात [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dd18-dgtr@gov.in](mailto:dd18-dgtr@gov.in) तथा [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी संबंधित सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर, विहित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नामित प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in> पर नियमित निगरानी रखने की सलाह दी जाती है।

**ड. समय-सीमा**

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6 (4) के तहत सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों अर्थात [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dd18-dgtr@gov.in](mailto:dd18-dgtr@gov.in) तथा [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

#### **८. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और /अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. अगोपनीय रूपांतरण को ऐसी सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याम विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **९. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

36. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

१०. **असहयोग**

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2021

**Case No. AD (SSR)- 19/2020**

**Subject: Sunset Review of anti-dumping duty imposed on imports of Tyre Curing Presses for Tyres originating in or exported from China PR.**

**F. No. 7/37/2020-DGTR.**—M/s Larsen & Toubro Limited (hereinafter referred to as the “Applicant”), on behalf of the domestic industry, has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), requesting for initiation of sunset review investigation concerning imports of Tyre Curing Presses also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for tyres (hereinafter referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration or “PUC”’) originating in or exported from China (hereinafter referred to as ‘subject country’).

2. The Applicant has alleged likelihood of continuation of dumping of subject goods, originating in and exported from China PR, and recurrence of injury to the domestic industry in the event of cessation of Anti-dumping duty, and has requested for sunset review investigations on the import of the subject goods originating in or exported from China PR.

**A. Background**

3. Anti-dumping duties were first levied on the imports of subject goods from China in 2009, following the preliminary findings which were issued by the Authority in March 2009. Thereafter, the Authority issued final findings in October 2009 and Ministry of Finance imposed duties vide Notification No. 01/2010-Customs dated 8<sup>th</sup> January 2010.

4. A mid-term review was initiated on 23rd May 2011 and the final findings were issued on 29<sup>th</sup> March 2012 wherein Six Day Light Curing Press for curing bicycle tyres was excluded from the ambit of duty. The Ministry of Finance vide notification no. 26/2012 - Customs (ADD), dated 14<sup>th</sup> May, 2012 implemented the recommendation.

5. A sunset review was initiated on 07th January 2015. The anti-dumping duties were extended for a period upto 7th January 2016 vide notification number 06/2015-Customs (ADD) pending outcome of the review. The Authority issued final finding published vide notification No.15/22/2014-DGAD dated 5th January 2016 recommending extension of anti-dumping duties for 5 years. The Ministry of Finance extended the anti-dumping duty vide Notification No. 11/2016-Customs (ADD) dated 29th March 2016.

**B. Product under consideration**

6. The product under consideration in the present application, as defined in the last sunset review investigation is “Tyre Curing Presses” also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for tyres, excluding Six Day Light Curing Press for curing bi-cycle tyres.

7. The product under consideration is classified under chapter 84 of the Customs Tariff Act, 1975 and subheading 84775100. However, the custom classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

8. The domestic industry has adopted PCNs for the purpose of present investigation on the basis of (a) diameter of the tyre that can be cured and (b) whether the machine is hydraulic or mechanical for the purpose of determination of dumping margin, price undercutting and injury margin.

**C. Like Article**

9. The Applicant has claimed that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the goods being imported into India. Subject goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. For the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant is being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from China PR.

**D. Domestic industry & standing**

10. The application for the sunset review has been filed by M/s Larsen & Toubro Limited on behalf of the domestic industry. As claimed by the applicant their share accounts for around 87% of the gross domestic production. The applicant has also claimed that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is it related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or an importer of the subject goods in India. On the basis of the information on record, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) and the application fulfils the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

**E. Basis of likelihood of recurrence of dumping**

11. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The prices or constructed value of the product under consideration in market economy appropriate third country or the prices from such third country to other countries, including India has neither been made available by the Applicant, particularly in view of the nature of the product, nor is this information available with the Authority from any public source. Thus, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, considering the cost of production in India, selling, general & administrative expenses and reasonable profits. Separate normal value has been prepared for different presses.

12. The Applicant has claimed export prices on the basis of Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) transaction-wise import data. Price adjustments has been made for ocean freight, insurance and inland freight and forwarding charges.

13. Considering the estimates of normal value and the export price as mentioned above, dumping margin has been determined. Separate dumping margin has been determined for each type of press. The resultant weighted average dumping margin is positive. There is *prima facie* evidence that the product has been exported to India at a price below the normal value, showing that the subject goods originating in or exported from China PR are being exported at dumped prices.

**F. Continuation of injury and causal link**

14. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The volume of imports of subject goods from subject country has increased in the POI in absolute terms. Imports have also increased during the POI in relation to production & consumption as compared to preceding year. Imports are undercutting the domestic prices without applicable ADD. Though the performance of the domestic industry has improved till 2018-19 from the base year, the same has declined during the POI and thus, the domestic industry remains vulnerable due to dumping of the subject goods from the subject country.

**G. Likelihood of recurrence of Injury and Casual Link**

15. The Authority notes that there is *prima facie* evidence of continuation of dumping and likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in the event of cessation of ADD, considering the volume and price of imports of subject goods from subject country, positive dumping and injury margin, price undercutting, and the performance of the domestic industry in the duty-free market (which does not attract ADD). Further, the applicant has claimed that the Chinese producers are holding significant freely disposable production capacities along with their high export orientation. It

is *prima facie* noted that there is likelihood of continuation of dumping and consequential injury to the domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duties.

**H. Initiation of Sunset Review**

16. In view of the duly substantiated written application by the Domestic Industry, and having satisfied, on the basis of the *prima facie* evidence about the likelihood of dumping and consequent injury to the Domestic Industry, and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority hereby initiates investigation to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR and to examine whether the expiry of existing duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry.

**I. Subject Country**

17. The country involved in the present investigation is China PR.

**J. Period of Investigation (POI)**

18. The Applicant had initially proposed period of investigation as 1st April 2019 to 30 June, 2020 and injury investigation period as 1st April 2016 to 31st March 2017, 1st April 2017 to 31st March 2018, 1st April 2018 to 31st March 2019 and the period of investigation. Later on, the Applicant requested to extend the POI till 30th September, 2020 and furnished the data till 30th June, 2020. The Authority however considers it appropriate, having regard to Rule 2(da), and explanation to rule 22, to fix the period 1st April 2019 - 30 September 2020 (18 months) as the period of investigation (POI), and the period 1st April 2016 to 31st March 2017, 1st April 2017 to 31st March 2018, 1st April 2018 to 31st March 2019 and the period of investigation as the injury investigation period. The Authority considers that the period of investigation is appropriate, considering the rule and inclusion of one full accounting year of the domestic industry in the investigation period.

**K. Procedure**

19. The present sunset review covers all aspects of the sunset review final findings published vide notification no No.15/22/2014 dated 5th January, 2016. The Authority would also undertake likelihood analysis of dumping and Injury as required.

20. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**L. Submission of Information**

21. In view of the special circumstances arising out of COVID- 19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dd18-dgtr@gov.in](mailto:dd18-dgtr@gov.in) and [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

22. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in> for any updated information with respect to this investigation.

**M. Time Limit**

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dd18-dgtr@gov.in](mailto:dd18-dgtr@gov.in) and [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) within 37 days from the date of receipt of the notice as per as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**N. Submission of information on confidential basis**

28. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

30. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**O. Inspection of Public File**

36. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**P. Non-cooperation**

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt.Secy. and Designated Authority